

अब बहुत जल्द बदलने वाला है पीएमओ का पता !



नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी (पीएमओ) का पता

● 78 साल बाद नए जगह पर शिफ्ट होने वाला है प्रधानमंत्री कार्यालय

बदलने वाला है। वर्तमान में पीएमओ साउथ ब्लॉक में स्थित है जो अगले महीने एग्जिक्यूटिव एन्क्लेव में शिफ्ट हो जाएगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत तैयार किए गए इस नए एन्क्लेव में प्रधानमंत्री कार्यालय के अलावा कैबिनेट सचिवालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और एडवांस कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा भी होगी। गौरतलब है कि नया पीएमओ प्रधानमंत्री के आवास से ज्यादा नजदीक है। साउथ ब्लॉक स्थित पीएमओ में आधुनिक सुविधाओं की कमी है। वहीं, जगह की भी कमी महसूस की जा रही है। जानकारी के मुताबिक, नए पीएमओ का नामकरण भी कुछ नया किया जा सकता



जनता का होना चाहिए। यह मोदी का पीएमओ नहीं है। हाल ही में प्रधानमंत्री

मोदी ने गृह मंत्रालय और कार्मिक मंत्रालय के नए कार्यालय 'कर्तव्य भवन-3' का उद्घाटन करते हुए कहा कि प्रशासनिक मशीनरी अभी भी ब्रिटिश कालीन इमारतों से काम कर रही है, जहां रोशनी और वेंटिलेशन की कमी है सूत्रों के मुताबिक, नए पीएमओ को नया नाम भी दिया जा सकता है, जो 'सेवा' की भावना को दर्शाए। प्रधानमंत्री ने कहा था,पीएमओ जनता का होना चाहिए।संग्रहालय' का रूप दिया जाएगा। इस परियोजना के तहत राष्ट्रीय संग्रहालय और फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट के बीच समझौता हुआ है। सरकार का कहना है कि यह संग्रहालय भारत की सांस्कृतिक धरोहर है।

15 अगस्त पर ‘पाकिस्तान मोहल्ला’ का खात्मा !

● बीजेपीएमएलएपूर्णशमोदीकी मौजूदगीमेंस्वा गया नया नाम



अहमदाबाद/सुरत (एजेंसी)। गुजरात की हीरा नगरी में 79वें स्वतंत्रता दिवस पर बड़ा बदलाव हुआ। आजादी के बाद से पाकिस्तानी मोहल्ले के तौर पकारे जाने वाले एक क्षेत्र को नया नाम दिया गया। सुरत शहर के रांदेर इलाके के रामनगर में स्थित पाकिस्तान मोहल्ले का नाम आधिकारिक तौर पर बदल दिया गया। बीजेपी के विधायक और पूर्ण मंत्री पूर्णेश मोदी की मौजूदगी में इस क्षेत्र का नाम पाकिस्तान मोहल्ले से हिन्दुस्तानी मोहल्ला किया गया। भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने स्थानीय निवासियों की उपस्थिति में एक नए साइनबोर्ड का उद्घाटन किया। नए बदलाव के बाद अब लोग अपने दस्तावेजों में

पाकिस्तानी मोहल्ले की जगह पर नए नाम को अपडेट कराने के लिए उत्सुक है। सोमवार से इसके लिए लोग आवेदन जाम कर रहे, ताकि उनके आधार के पते से पाकिस्तानी शब्द हट जाए। सुरत में इस मोहल्ले की जड़ें विभाजन से जुड़ी हुई थीं। जब कई सिंधी शरणार्थी सुरत में आकर बस गए थे। उन्होंने रामनगर नाम से एक कॉलोनी बसाई थी, जिसमें लगभग 600 घर थे। इस समय के साथ इस कॉलोनी का एक हिस्सा पाकिस्तान मोहल्ले के नाम से लोकप्रिय हो गया। इस इलाके का नाम बदलने के पहले के प्रयास में आंतरिक चौराहे का नाम हेमू कलानी चौक रखा गया, लेकिन यह काफी लोकप्रिय नहीं हो पाया।

यूपी चुनाव : मिशन 2027 के लिए कांग्रेस का नया ‘दांव’

पंचायत से विधानसभा तक संगठन पर फोकस ‘वोट चोरी’ बनेगा चुनावी मुद्दा, तैयारी हुई तेज



मेरठ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस एक बार फिर बड़ा दांव खेलने की तैयारी में जुट गई है। 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए पार्टी ने न सिर्फ 403 सीटों पर अपनी रणनीति बना ली है, बल्कि इस बार संगठन को जमीनी स्तर से खड़ा करने की ठोस योजना भी तय की है। कांग्रेस का मकसद साफ है पंचायत से लेकर विधानसभा तक ऐसा ढांचा खड़ा करना जो सिर्फ चुनावी मौसम में नहीं, बल्कि हर वक्त सक्रिय रहे। कांग्रेस ने 2027 की रणनीति का आधार बनाया है ‘संगठन सुजन अभियान’। इसके तहत बृथ से लेकर मंडल स्तर तक पूरी संरचना को नया रूप दिया जा रहा है। हर विधानसभा क्षेत्र को तीन श्रेणियों ए, बी और सी में बांटकर अलग-अलग रणनीति बनाई गई है। ब्लॉक और वार्ड स्तर पर नई नियुक्तियां की जा रही हैं।

● कांग्रेस का फोकस मुस्लिम, दलित और पिछड़े समाज पर- कांग्रेस ने संकेत दे दिए हैं कि उसकी राजनीति सिर्फ पारंपरिक वोट बैंक तक सीमित नहीं रहेगी। पार्टी मुस्लिम समाज के साथ-साथ दलित और पिछड़े वर्ग पर भी विशेष ध्यान देने जा रही है। हर जिले में ‘संगठन सुजन कोऑर्डिनेटर’ नियुक्त होंगे, जो लगातार रिपोर्ट देंगे। वहीं पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेताओं को जिला-दर-जिला जिम्मेदारी दी जा रही है ताकि जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जा सके।

रेल की चेन खींची तो सीधा पहुंचेंगे जेल

भोपाल डिविजन में सिर्फ 7 महीने में 3,383 लोगों ने की चेन पुलिंग, हजारों पर कार्रवाई

भोपाल (नप्र)। अगर आप सोचते हैं कि ट्रेन की अलार्म चेन खींचना मामूली बात है, तो यह आंकड़े आपको सोच बदल देंगे। भोपाल रेल मंडल में केवल जुलाई 2025 तक 3,383 बार अलार्म चेन खींची गई और इनमें से 2,981 मामलों में यात्रियों पर कार्रवाई हो चुकी है। कई को जमाना भरना पड़ा तो कुछ को जेल की हवा तक खानी पड़ी। रेलवे ने साफ कर दिया है कि अब इस लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय रेल ने यह सुविधा यात्रियों की सुरक्षा और आपातकालीन मदद के लिए दी है, लेकिन हाल के दिनों में लोग इसे शरारत या व्यक्तिगत सुविधा के लिए इस्तेमाल करने लगे हैं। कोई यात्री देर से स्टेशन पर पहुंचा, किसी का परिजन छूट गया या फिर गलत डिब्बे में बैठने की वजह से ट्रेन रोकनी थी, ऐसे कारणों से अलार्म चेन खींचने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रानी कमलापति, भोपाल, इटारसी, विदिशा, बीना, हरदा, गुना और शिवपुरी जैसे बड़े स्टेशनों पर यह समस्या सबसे ज्यादा सामने आई है। वरिष्ठ मंडल सुरक्षा



आयुक्त डॉ. अभिषेक के निर्देश पर रेलवे सुरक्षा बल ने अब चेकिंग और जागरूकता अभियान तेज कर दिया है। यात्रियों को बताया जा रहा है कि अलार्म चेन का गलत इस्तेमाल न केवल अपराध है बल्कि यह सैकड़ों यात्रियों की यात्रा को प्रभावित कर देता है।

कांग्रेसनेता को रास नहीं आया पीएम मोदी का भाषण

बेंगलुरु (एजेंसी)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद बीके हरिप्रसाद ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भारतीय तालिबान करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। हरिप्रसाद का यह बयान उस वक्त आया है 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से संबोधन में संघ की सराहना की थी। न्यूज एजेंसी से बातचीत में हरिप्रसाद ने कहा,आरएसएस देश में शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि संघ भारतीय तालिबान है और प्रधानमंत्री उसकी प्रशंसा कर रहे हैं।



झूठे आरोपों से डरता नहीं है चुनाव आयोग

● हम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे ● कहा-न पक्ष-न विपक्ष, हमारे लिए तो सब समकक्ष

नई दिल्ली (एजेंसी)। बिहार में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेसिव रिवीजन शुरू होने के बाद से लगातार कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत तमाम विपक्षी दल चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। वोट चोरी और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी जैसे आरोपों का सामना कर रहे चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी आरोपों का सिलसिलेवार जवाब दिया। इस साल 18 फरवरी को चुनाव आयुक्त से मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभालने के बाद सीईसी ज्ञानेश कुमार की यह पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जिसमें उन्होंने आयोग के ऊपर लगातार किए जा रहे हमलों का करारा जवाब दिया और बताया कि बिहार में क्यों एसआईआर हो रहा है।



● बिहार में क्यों हो रहा एसआईआर, यह भी बताया- बिहार में मतदाता पुनरीक्षण को लेकर लगातार उठाए जा रहे सवाल पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, पिछले दो दशकों से लगभग सभी राजनीतिक दल मतदाता सूची में सुधार की मांग करते रहे हैं। इसी मांग को पूरा करने के लिए चुनाव आयोग ने गहन पुनरीक्षण की शुरुआत बिहार से की है। एसआईआर की प्रक्रिया में सभी मतदाता, बृथ लेवल ऑफिसर और सभी राजनीतिक दलों द्वारा नामित 1.6 लाख बीएलओ ने मिलकर एक प्रारूप सूची तैयार की है।

एलएलबी छात्र की हत्या करने वाले अरेस्ट

3 निगरानीशुदा बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर की थी वारदात, अलग-अलग स्थानों पर काटी फरारी

भोपाल (नप्र)। भोपाल में पेट्रोल पंप पर पहले पेट्रोल डलवाने के विवाद में लॉ स्टूडेंट के सीने में छुरी मारकर हत्या करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने वारदात के बाद सीहोर के कुबेरेश्वर धाम सहित मंडीदीप, बैरसिया और अन्य स्थानों पर फरारी काटते रहे। पुलिस टीम लगातार उनका पीछा कर रही थी। भोपाल लौटते ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी गंभीर अपराध दर्ज हैं। थाना प्रभारी महेश लिखरे ने बताया कि घटना 6 अगस्त की सुबह करीब 4 बजे की है। फरियादी अनमोल दुबे अपने दोस्त संस्कार बबले (22) के साथ एक्टिवा पर पेट्रोल भरवाने पेट्रोल पंप पहुंचे थे। इसी दौरान एक्टिवा पर आए तीन बदमाशों ने पहले पेट्रोल डलवाने की बात को लेकर विवाद शुरू कर दिया। बदमाशों ने गाली-गलौज करते हुए दोनों दोस्तों को धमकाया और अचानक हमला कर दिया।



बीच-बचाव करने आए अनमोल पर भी छुरी से हमला किया गया, जबकि संस्कार के सीने और माथे पर वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। अस्पताल ले जाने पर

उसकी मौत हो गई। संस्कार इंदौर का रहने वाला था और प्राइवेट कॉलेज से बीए एलएलबी की पढ़ाई कर रहा था। घटना के बाद अयोध्या नगर पुलिस ने तत्काल हत्या का केस दर्ज कर तीन अलग-अलग टीमों गठित कीं। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से उनकी पहचान की थी।

हत्या, लूट, चोरी, मारपीट जैसे केस दर्ज- गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य आरोपी संजु सेन (24) निवासी पूजा कॉलोनी करोंद निशातपुरा है, यह थाने का निगरानी शुदा बदमाश है। इसके खिलाफ हत्या, लूट, चोरी और मारपीट जैसे कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। दूसरा आरोपी दीपक वंशकार (24) आदर्श अस्पताल के पीछे करोंद, निशातपुरा है, इसके खिलाफ 9 अपराध दर्ज हैं। वहीं तीसरा आरोपी शुभम उर्फ नरसिमा (25) करोंद, निशातपुरा का रहने वाला है, इसके खिलाफ 3 अपराध दर्ज हैं।

कपड़ा-फुटवियर से लेकर घी-मक्खन तक हो जाएंगे सस्ते

● जीएसटी प्रणाली में शुरू हुई बदलाव की तैयारी, होगा बड़ा असर

नई दिल्ली (एजेंसी)। जीएसटी प्रणाली से 12 और 28 प्रतिशत कर वाले स्लैब को समाप्त करने पर कपड़ा-फुटवियर से लेकर घी-मक्खन तक सस्ते हो जाएंगे। 1000 रुपये से अधिक कीमत वाले शर्ट-पैट और फुटवियर खरीदने पर 12 प्रतिशत टैक्स लगता है, जबकि 1000 रुपये से कम कीमत वाले शर्ट-पैट व फुटवियर पर पांच प्रतिशत, जीएसटी देना पड़ता है। अब सभी प्रकार के शर्ट-पैट और फुटवियर पर पांच प्रतिशत टैक्स लगेंगे। सरकार की ओर से जारी नए प्रस्ताव के मुताबिक, 12 प्रतिशत के स्लैब में शामिल 99 प्रतिशत उत्पादों को पांच

प्रतिशत कर की श्रेणी में शामिल कर दिया जाएगा। ऐसे में दैनिक रूप में इस्तेमाल होने वाले सैकड़ों उत्पादों पर अब पहले के मुकाबले सात प्रतिशत तक कम टैक्स लगेगा और ग्राहकों को कम कीमत चुकानी होगी। इनमें मुख्य रूप से ड्राइ फ्रूट, सभी प्रकार के पैकड नमकीन, प्रोसेस्ड फ्रूड, चटनी, जैम, जेली, पैकड नारियल पानी, पैकड जूस, 20 लीटर वाली पानी की पैकड बोतल, पास्ता, पेंसिल, टूथ पाउडर, जूट व काटन का हैंडबैग, शॉपिंग बैग, मोमबत्ती, टायलेट में शामिल होने वाले सामान,

मच्छरदानी, म्यूनीज, विभिन्न प्रकार की आयुर्वेदिक व अन्य दवाइयां, पास्ता, परदा, किचनवेयर, फसल काटने वाली मशीन सस्ते होंगे।



● 12 की जगह पांच प्रतिशत वसूला जाएगा जीएसटी- 12 प्रतिशत की जगह इन उत्पादों पर अब पांच प्रतिशत जीएसटी वसूला जाएगा। ऐसा नहीं है कि इन उत्पादों को जीएसटी से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। जीएसटी राजस्व में 28 प्रतिशत के स्लैब की हिस्सेदारी 11 प्रतिशत है और इसके उत्पादों को 18 प्रतिशत में शामिल कर दिया जाएगा। 28 प्रतिशत में काफी कम उत्पाद शामिल हैं। इनमें से कई उत्पादों पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगाने का प्रस्ताव है। वित्त वर्ष 2024-25 में जीएसटी का मासिक औसत संग्रह 1.8 लाख करोड़ रहा है। जीएसटी राजस्व में 12 प्रतिशत स्लैब की हिस्सेदारी पांच प्रतिशत है और इस हिसाब 1.8 लाख करोड़ में उनकी हिस्सेदारी नौ हजार करोड़ रुपये होती है। डेलाइट के पार्टनर (अप्रत्यक्ष कर) हरप्रीत सिंह ने बताया कि सरकार के नए प्रस्ताव को देखते हुए राजस्व नुकसान का हिसाब लगाया जा रहा है और मोटे तौर पर यह नुकसान मासिक रूप से चार हजार करोड़ रुपये का दिख रहा है। 28 प्रतिशत में शामिल कई उत्पादों को सरकार 40 प्रतिशत में डाल सकती है। अभी इस दिशा में विचार चल रहा है। सिंह ने बताया कि रोजमर्रा के उत्पादों के सस्ता होने से कुछ समय बाद इनकी बिक्री में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है।

